टिप्पणियाँ

2

भारत में आर्थिक नियोजन

भारत अपनी जनसंख्या के कारण अनेक समस्याओं का सामना करने वाला एक विशाल देश है। अंग्रेजों ने देश पर लगभग दो शताब्दी तक शासन किया और अपने लाभ के लिए इसके संसाधनों का दोहन किया और देश को अत्यंत गरीबी में लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो 'स्वतंत्रता' के अतिरिक्त गर्व करने अथवा प्रसन्न होने के लिए कुछ भी नहीं था। भारत सरकार के सामने अनेक समस्याएं थीं। बड़ी संख्या में गरीबी के अतिरिक्त भोजन की कमी तथा मुद्रा स्फीति की समस्या थी। निरक्षरता, स्वास्थ्य चिकित्सा की कमी, आधारिक संरचना की कमी आदि देश के सामने गंभीर समस्याएं थीं। दीर्घकालीन व्यूह रचना के रूप में इन समस्याओं के समाधान के लिए विकास के लिए 'नियोजन' ही उत्तर था।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप:

- नियोजन की परिभाषा दे सकेंगे;
- नियोजन की आवश्यकता व्याख्यायित कर सकेंगे;
- नियोजन के उद्देश्यों की सूची बना सकेंगे;
- भारत में नियोजन की व्यूह रचना का विवरण दे सकेंगे;
- नई आर्थिक नीति का उल्लेख कर सकेंगे;
- नियोजन के विभिन्न उद्देश्यों के संदर्भ में हमारे योजनाकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को रेखांकित कर सकेंगे;
- योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की व्याख्या कर सकेंगे; तथा
- योजनागत लक्ष्यों की कमियों तथा अनुपलब्धियों की पहचान कर सकेंगे।

2.1 आर्थिक नियोजन का अर्थ

आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं–

(i) अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याओं की सूची तैयार करना।

(ii) प्राथमिकता के आधार पर सूची का पुनः क्रम तैयार करना। सर्वोच्च विचारणीय विषय, जिसका तुरंत समाधान आवश्यक है, उसे प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए तथा इसी प्रकार।

(iii) अगला चरण उन समस्याओं को पहचानना है, जिनको तुरंत अल्पकाल में हल करना है तथा अन्य समस्याएं जिनका समाधान दीर्घ काल में करना है।

(iv) इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को निश्चित करना। लक्ष्य कोई एक विशेष समय अवधि हो सकता है, जिसमें समस्या को हल करना है। यदि समस्या का समाधान दीर्घ काल में करना है तो यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रथम वर्ष में कितनी समस्या हल की जाएगी (जैसे एक वर्ष अथवा छह महीने) और इसी प्रकार। द्वितीय लक्ष्य कोई एक मात्रा हो सकती है, जिसे प्राप्त करना है। जैसे, उत्पादन, सरकार मात्रा में लक्ष्य निश्चित कर सकती है।

(v) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा का आकलन करना। संसाधनों में वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधन आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(vi) संसाधनों को प्रयोग करना एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसका अभिप्राय है कि योजनाकारों को आवश्यक संसाधनों के प्रबंध के स्रोतों का ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, योजना के वित्त की व्यवस्था के लिए योजनाकारों को बजट बनाना चाहिए तथा वित्तीयन के विभिन्न स्रोतों को बताना चाहिए। जब सरकार योजना बनाती है तो इसके लिए कोष प्राप्ति के मुख्य स्रोतों में से एक कर राजस्व होता है। एक व्यवसायी के लिए, वित्त के स्रोतों में एक बैंक से ऋण होता है। जब कोषों के विभिन्न स्रोत उपलब्ध होते हैं तो योजनाकार को यह भी निश्चित करना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक स्रोत से कितना कोष एकत्र करना है।

योजना के प्रस्ताव को पूरा करने के लिए मानव संसाधन को प्रयोग करना एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य है। योजनाकार को मानव शक्ति के प्रकार और कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का आकलन करना चाहिए। इस आवश्यकता का उचित अनुमान प्रारंभ में ही दे देना चाहिए। इसी प्रकार, भौतिक संसाधनों का भी एक उचित अनुमान उपलब्ध करा देना चाहिए। भौतिक संसाधनों में ऑफिस की इमारतें, मोटर गाड़ियां, फर्नीचर, लेखन-सामग्री आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(vii) एक बार जब संसाधनों का प्रबंध हो जाए तो इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर चीज सुचारू रूप से चल रही है और यदि कोई त्रुटियां हैं तो उन्हें ठीक करने अथवा

कार्य करने के ढंग को रूपांतरित करने के लिए जब तक अंतिम उपलब्धि प्राप्त न कर ली जाएं, सामयिक पुनरावलोकन करना चाहिए।

2.2 भारत में आर्थिक नियोजन

भारत ने अपनी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए पंचवर्षीय नियोजन पद्धति को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं के विषय में आपको पहले ही बताया जा चुका है। दोबारा ध्यान दिलाने के लिए इन समस्याओं में बड़ी संख्या में गरीबी तथा असमानता, कृषि में निम्न उत्पादकता, खाद्यान्नों की कमी, औद्योगिक तथा आधारिक संरचना के विकास की कमी आदि शामिल हैं, क्योंकि इसका दीर्घकालीन हल किया जाना है। भारत सरकार ने 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को अपनाया। दिए हुए संसाधनों तथा संसाधनों का प्रबंध करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए महत्त्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए उनकी सूची बनाने का विचार था। फिर, क्या हुआ है इसका पांच वर्षों के बाद पुनरावलोकन करना तथा अगली पंचवर्षीय योजना अवधि में तद्नुसार त्रुटियों में सुधार करना और इसी प्रकार। भारतीय नियोजन के कुछ महान शिल्पकारों में जवाहरलाल नेहरू, पी.सी. महलानोबीस, बी. आर गडगिल, वी.के.आर.वी. राव सम्मिलित हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेहरू जी ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की।

योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना तथा उनको प्रभावशाली तथा संतुलित ढंग से प्रयोग करने के लिए सुझाव देना था। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना (FYP) 1951-56 की अवधि के लिए तैयार की। 2014 तक भारत में ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण होकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना (FYP) चल रही है, इसके साथ भारत नियोजन के 60 वर्ष से अधिक का अनुभव कर चुका है।

2.3 भारत में नियोजन के उद्देश्य

भारत में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं–

1. आर्थिक संवृद्धि
2. रोजगार में वृद्धि
3. आय की असमानताओं (विषमताओं) में कमी
4. गरीबी में कमी
5. अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण
6. सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना

आइए, अब हम इन उद्देश्यों की एक-एक करके चर्चा करें।

1. आर्थिक संवृद्धि

आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने से अभिप्राय है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में प्रत्येक वर्ष लक्षित दर के अनुसार वृद्धि हो। वास्तविक राष्ट्रीय आय एक दिए गए वर्ष की कीमतों पर अथवा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की औसत आय है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति/परिवार के तथा पूरे समाज के उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए वास्तविक अर्थों में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय दोनों बढ़नी चाहिए, क्योंकि आय क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, आय में वृद्धि लोगों और देश की क्रय शक्ति को बढ़ाती है। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अधिक वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकेंगे। पूरा देश विदेशों से अपनी खरीद के लिए जिसे आयात कहते हैं, को भुगतान कर सकते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का भी अर्थ है कि उत्पादन का स्तर अथवा उत्पादन की मात्रा पहले से अधिक है। यहां उत्पादन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में उत्पादन जैसे–कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक वर्ष उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करनी है। उत्पादन की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को आधारिक संरचना तथा पूंजीगत स्टॉक बनाने के लिए निवेश की दर को बढ़ाना आवश्यक है। आधारिक संरचना में बिजली परियोजनाएं, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, दूरसंचार, भवनों आदि को सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत स्टॉक में प्लांट, मशीनरी, बैंकिंग तथा बीमा आदि सम्मिलित हैं। इन सभी में निवेश वास्तविक आय में आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए देश के योजनाकारों ने जनसंख्या में वृद्धि तथा वस्तुओं और सेवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में संवृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए।

2. रोजगार में वृद्धि

रोजगार से अभिप्राय श्रम शक्ति का लाभजनक आर्थिक क्रिया, जैसे–वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में संलग्न होने से है। उत्पादन प्रक्रिया द्वारा आय का सृजन होता है, जहां उत्पादन प्रक्रिया में परिवारों द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन के साधनों का रोजगार सम्मिलित है। आप जानते हैं कि उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन/उद्यम शामिल हैं। ये साधन देश के परिवारों के स्वामित्व में होते हैं, क्योंकि साधन दुर्लभ हैं तथा संसाधनों की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार के लिए ऐसे अवसरों का सृजन करना आवश्यक हो जाता है कि इनका उचित उपयोग हो सके। किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता उसके पास साधन-संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि उत्पादन के इन साधनों को रोजगार मिल जाए तो आवश्यक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। फिर उत्पादन के मूल्य को साधनों के बीच उनकी आय के रूप में, श्रम के लिए मजदूरी, भूमि तथा भवन के स्वामी को लगान, पूंजी के स्वामी को ब्याज तथा उद्यमी को लाभ के रूप में बांटा जा सकता है। यदि देश उत्पादन के साधनों को लाभजनक क्रियाओं में लगाने के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने में असमर्थ है तो आवश्यक उत्पादन की मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता और इसलिए आय का सृजन नहीं हो सकता। देश में श्रम संसाधन का ही उदाहरण

लीजिए। आप जानते हैं कि देश की जनसंख्या जो 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, श्रम शक्ति की पूर्ति करती हैं। जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि के कारण श्रम शक्ति में लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। उनमें से अधिकतर शिक्षित भी होते हैं। यदि रोजगार पाने के काफी अवसर नहीं है तो वे बेरोजगार रहेंगे तथा उनका उपयोग नहीं हो पाएगा। वास्तव में, भारत में बेरोजगारी की स्थिति बहुत बुरी है। उत्पादन में अनुरूप वृद्धि किए बिना उपभोग में वृद्धि करने के अतिरिक्त, बेरोजगारी विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे–गरीबी तथा अपराध का भी एक कारण है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के योजनाकारों ने रोजगार सृजन को पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य रखा।

पाठगत प्रश्न 2.1

1. आर्थिक संवृद्धि का अर्थ है–

   (अ) वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि (ब) विषमताओं को दूर करना

   (स) कीमत स्तर में वृद्धि (द) उपर्युक्त में कोई नहीं

2. राष्ट्रीय आय में वृद्धि इसके द्वारा हो सकती है–

   (अ) जनसंख्या में वृद्धि (ब) निवेश की दर में वृद्धि

   (स) बेरोजगारी में वृद्धि (द) कीमत स्तर में वृद्धि

3. उत्पादन के साधनों के स्वामी कौन हैं?

   (अ) सरकार (ब) शेष विश्व

   (स) परिवार (द) फर्म तथा उद्योग

4. श्रम शक्ति जनसंख्या के इस आय वर्ग से आती है–

   (अ) 4 से 14 (ब) 60 से 75

   (स) 10 से 15 (द) 15 से 59

3. आय की विषमताओं में कमी

भारत अपनी जनसंख्या के विविध आर्थिक मानदंडों वाला देश है। इससे अभिप्राय है कि आय के स्तर के संदर्भ में भारत में समानता नहीं है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न आय वर्ग वाला है, जो गरीब कहलाता है, जबकि कुछ बहुत ऊंची आय स्तर वाले धनवान हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से आय की असमानता एक प्रमुख चिंता का विषय है, बिना उनकी जाति अथवा धर्म पर विचार किए स्त्रियां आय के मानदंड में सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं।

इसी प्रकार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या भारतीय समाज के सीमांतित वर्ग से संबंध रखती है, क्योंकि वे विकास के सूची स्तंभ में सबसे निचले स्तर पर हैं। आय की असमानता का प्रमुख कारणों में से एक परिसंपत्तियों के स्वामित्व जैसे–प्रति व्यक्ति भूमि जोत तथा पैतृक चल और अचल संपत्ति आदि का असमान वितरण है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा कृषि में कार्य करती है परंतु कुछ बड़े भूमिपति हैं तथा अधिकांश छोटे कृषक और कृषि मजदूर हैं। उन्हें कृषि मजदूर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जोतने के लिए उनके पास अपनी भूमि नहीं है तथा दैनिक अथवा साप्ताहिक मजदूरी के आधार पर कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उनकी अपनी निरक्षरता तथा अपने आपको संगठित करने की कमी के कारण उनकी स्थिति बहुत खराब है। एक तो उनकी निम्न आय के कारण उनके पास अपनी पीढ़ियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं होता।

दूसरी तरफ भूस्वामी अपनी संपत्तियों पर अधिक आय कमाते हैं और उत्तराधिकार नियमों के अस्तित्व में होने के कारण, संपत्ति उनकी भावी पीढ़ी के पास ही रहती है। इसलिए, देश में क्रमशः संपत्ति रखने तथा निजी संपत्ति के अभाव में धनवान, धनवान ही रहता है और गरीब, गरीब ही रहता है। भारत इस विषमता से बुरी तरह प्रभावित है। गरीब लोग क्रय शक्ति के अभाव में बाजार को सहारा नहीं दे पाते हैं, जबकि अमीरों के पास अधिक क्रय शक्ति के कारण उनके बेकार के उपभोग में वृद्धि होती है। अधिकतर सामाजिक बुराइयां विषमता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अतः हमारे योजनाकारों ने नियोजन द्वारा आय में विषमताओं को कम करने का उद्देश्य रखा।

4. गरीबी में कमी

भारत में नियोजन का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य 'गरीबी में कमी करना' है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक गरीब था। सरकारी अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2014 तक भारत की जनसंख्या का लगभग 27 से 28 प्रतिशत गरीबी में रहता है। गरीबी और बेरोजगारी के पाठ में आप, भारत में गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, के बारे में जान पाएंगे। इस समय हम गरीबी के विचार को ऐसी स्थिति तक सीमित रखें, जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में असमर्थ है। देश में ऐसे बहुत लोग हैं, जिनको दिन में दोनों समय का भोजन नहीं मिलता है। रोजगार का अभाव गरीबी का एक प्रमुख कारण है। इसमें आय और संपत्ति की विषमताओं से और वृद्धि हो जाती है। गरीबी को मानवीय गरिमा पर अभिशाप कहा जाता है तथा इसने विश्व में भारत की छवि को गंभीर रूप से कलंकित किया है। विकसित देश, भारत को अपनी गरीबी हटाने में असमर्थता के कारण, गंभीरता से नहीं लेते। उचित नियोजन देश से गरीबी को पूरी तरह से हटा सकता है।

5. अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण

भारत विदेशी शक्तियों द्वारा लगातार शोषण वाला देश रहा है, जैसे–मुगल, जिन्होंने दो सौ वर्षों से अधिक शासन किया तथा अंग्रेज जिन्होंने अगले दो सौ वर्ष शासन किया। विशेष रूप से,

अंग्रेजों ने जब 1947 में सत्ता भारत सरकार को सौंपी, उन्होंने देश को अत्यंत गरीबी तथा अल्प विकसित अवस्था में छोड़ा। ऐतिहासिक कारणों से, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत कार्य करने के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकी। यह कृषि और औद्योगिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था ही रही। नई प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी का विकास में सुधार नहीं हुआ। भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता तथा औद्योगिक विकास में कमी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव एक प्रमुख कारण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और उसके पश्चात् अनेक वर्षों तक अल्पविकसित औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रक तथा अच्छी शिक्षा और जनसंख्या में कौशल-विकास के अभाव के कारण भारत के GDP में प्रमुख योगदान देने वाला व्यावसायिक ढांचे का झुकाव भी कृषि की ओर ही रहा। इसलिए इस प्रवृत्ति को उल्टा करने के लिए मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा उद्योगों और सेवा क्षेत्रक के विकास द्वारा भारत की GDP की संरचना में परिवर्तन करना आवश्यक है। इसे अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण द्वारा किया जा सकता है।

6. सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना

भारतीय नियोजन का उद्देश्य समाज का समाजवादी प्रारूप प्राप्त करना भी था। इसे अपनी जनसंख्या को सामाजिक न्याय तथा समानता सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में, उपर्युक्त सभी उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। परंतु धारणीय सामाजिक न्याय तथा आय के वितरण की समानता के लिए जिनके कारण तथा विषमता बनी हुई हैं तथा औद्योगिक और सेवा क्षेत्रक के विकास में बाधक है और कृषि में निम्न उत्पादकता रही है। विभिन्न क्षेत्रकों में सुधार की आवश्यकता है। वर्षों पुरानी रीतियों में सुधार करना एक आवश्यक शर्त है। अत: योजनाकारों ने कृषि तथा आर्थिक नीति में सुधार लाने के लिए सोचा, ताकि वे विकास के लाभों के लिए संवृद्धि और समान वितरण को सुगम बना सकें।

पाठगत प्रश्न 2.2

1. आय की विषमताओं के कारणों में से एक है–

   (अ) निजी संपत्ति का अस्तित्व

   (ब) संपत्ति के समान वितरण का अभाव

   (स) उपर्युक्त दोनों

   (द) उपर्युक्त में कोई नहीं

2. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की GDP में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किस क्षेत्रक का अंश अधिक रहता था?

   (अ) उद्योग (ब) कृषि

   (स) सेवा (द) उपर्युक्त में कोई नहीं

2.4 नियोजन की आवश्यकता

नियोजन की आवश्यकता प्रश्न के बड़े भाग का उत्तर ऊपर स्वयं 'नियोजन के अर्थ' के अंतर्गत दे दिया गया है। वहां हमने कहा था कि नियोजन में प्रभावशाली कार्यान्वयन तथा संपादन के लिए विभिन्न चरण सम्मिलित होते हैं। वास्तव में, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने समस्याओं की संख्या बहुत अधिक है। प्रत्येक समस्या जटिल प्रकृति की है और उसका समाधान अल्प अवधि में नहीं किया जा सकता। गरीबी की समस्या का ही उदाहरण लीजिए। ऐसी कोई विधि नहीं है, जिसके द्वारा इस समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। सरकार को गरीबी से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या तथा उसकी प्रकृति को जानने के लिए आंकड़े का संग्रह करने चाहिए। भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्र और अनेक क्षेत्रों तक पहुंच के अभाव को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का संग्रह स्वयं एक बहुत बड़ा कार्य है। प्रजातंत्र में, सरकार वाद-विवाद के पश्चात् ही नीतियां बनाती है, जिसमें समय लगता है। पर्याप्त संसाधनों का प्रयोग करना और दीर्घ अवधि में कार्यक्रम को जारी रखने के लिए संसाधनों का प्रावधान करना, गरीबी की समस्या के समाधान के लिए ये दो मुख्य चीजें हैं। बिना उचित नियोजन के इसे नहीं किया जा सकता। व्यर्थ के खर्चों से बचने, लागत को न्यूनतम करने, लक्ष्य को तय समय में प्राप्त करने और संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए भी नियोजन आवश्यक है।

2.5 नियोजन की व्यूह रचना

व्यूह रचना से हमारा अभिप्राय नियोजन के अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही विधि/सूत्र का प्रयोग करने से है। प्रथम योजना अवधि 1951-56 में किसी विशेष व्यूह रचना का पालन नहीं किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा भोजन की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्नों की पूर्ति तत्कालिक विचारणीय विषय था। इस समय में भारत सरकार ने कृषि पर अधिक बल दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार, संवृद्धि की दर को प्राप्त कर लिया गया था, इसलिए भारत भविष्य में नियोजन के लिए एक दीर्घ अवधि वाली व्यूह रचना अपनाने की स्थिति में था।

तद्नुसार, द्वितीय योजना अवधि 1956-61 में विकास की व्यूह रचना को स्पष्ट रूप से बताया गया। व्यूह रचना इन पर बल देने के लिए थी–1. औद्योगीकरण, 2. औद्योगीकरण में भारी उद्योगों पर अधिक बल।

2.6 औद्योगीकरण की व्यूह रचना का औचित्य

गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक संवृद्धि आदि से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए भारतीय योजनाकारों ने देश में सामान्य रूप से औद्योगीकरण तथा विशेष रूप से भारी और मूलभूत उद्योगों की स्थापना की व्यूह रचना को अपनाया। औद्योगीकरण तथा भारी उद्योगों की व्यूह रचना के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं–

1. भारत की जनसंख्या कृषि पर अधिक निर्भर रही है, जिसके परिणाम है–ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़भाड़, भूमि पर दबाव, भूमि जोतों का विखंडन, जोतने के लिए भूमि की स्थिर मात्रा में अनुपलब्धता के साथ अल्प रोजगार तथा बेरोजगारी और जनसंख्या के बड़े भाग के पास प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता बहुत कम अथवा नहीं के बराबर। इसके परिणामस्वरूप भूमि के वितरण में विषमता उत्पन्न हुई है और अंतत: कृषि उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कृषि में संलग्न श्रम को उद्योगों में ले जाने तथा भूमि पर दबाव करने के लिए एक ही उत्तर है–औद्योगीकरण।

2. औद्योगिक गतिविधियां कृषि गतिविधियों की अपेक्षा कार्य के अधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। अत: औद्योगीकरण देश में बेरोजगारों को रोजगार पाने में अधिक सहायक होगा।

3. औद्योगीकरण स्वयं कृषि के विकास के लिए भी आवश्यक है। उद्योग कृषि से कच्चा माल प्राप्त कर प्रयोग करते हैं और कृषि क्षेत्र को औद्योगिक मशीनें तथा उपकरण, जैसे–पंप सेट, ट्रैक्टर, बिजली आदि की आवश्यकता होती है।

4. मूलभूत और भारी उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मूलभूत और भारी उद्योगों के उदाहरण हैं–लौह एवं इस्पात, एल्यूमीनियम, भारी रसायन, भारी विद्युत उपकरण आदि। ये पूंजीगत वस्तुओं वाले उद्योग होते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अन्य उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवश्यक मशीन तथा उपस्करों का उत्पादन करते हैं, जो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। अत: भारी उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं।

   यह ध्यान रखना चाहिए कि भारी उद्योगों की व्यूह रचना को अपनाने के पश्चात् भारत सरकार ने ऐसे उद्योगों की स्थापना तथा प्रबंध के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन किया। कुछ उदाहरण हैं–स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (SAIL), भारत एल्यूमीनियम कंपनी (BALCO), भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि. (BHEL), नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी (NALCO) आदि।

5. भारी और मूलभूत उद्योगों के अतिरिक्त भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्मय उद्योगों को विकसित करने पर भी बल दिया है। इन उद्योगों को निवेश की सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है और इनकी स्थापना निजी व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। इन उद्योगों के लाभों में सम्मिलित हैं–स्वयं रोजगार को प्रोत्साहन तथा रोजगार के अवसरों का सृजन, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, आय की विषमताओं में कमी लाना, क्योंकि यह व्यक्तियों आदि के स्वामित्व में हो सकती हैं।

2.7 नई आर्थिक नीति

जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारी उद्योग व्यूह रचना का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व तथा प्रबंध में किया गया। सरकार ने आधारिक संरचना के सृजन तथा उद्योगों की स्थापना के

लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान किए। यह प्रक्रिया तीन दशकों से अधिक चली। स्वयं सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन का मूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि कुछ को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र की आधे से अधिक इकाइयां घाटे में चल रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अत्यंत कुप्रबंध तथा श्रम संबंधित समस्याएं थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के इन सब दोषों को देखकर सरकार को एक बड़ा झटका लगा। विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता को, औद्योगीकरण के क्षेत्र में देश के सर्वांगीण विकास में कमी, गरीबी तथा बेरोजगारी को हटाने के लिए प्रमुख कारणों के रूप में देखा गया। इसलिए 1991 में, केंद्रीय सरकार एक नई आर्थिक नीति प्रस्ताव लाई। इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं–

(i) उदारीकरण

(ii) निजीकरण

(iii) वैश्वीकरण

यह नीति विकास के LPG मॉडल के नाम से भी विख्यात है।

उदारीकरण का अर्थ और आवश्यकता

उदारीकरण का अर्थ है, देश में उद्योगों की स्थापना तथा चलाने में सरकार द्वारा नियंत्रण एवं नियमों को हटाना। 1991 तक, सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयां व्यावहारिक रूप से सरकार के अंतर्गत थीं, यद्यपि वे स्वायत्त संस्थाएं कहलाती थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य करने में सरकार के मंत्रियों का बहुत हस्तक्षेप होता था। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिकरण और व्यावसायिक गुणवत्ता में गिरावट तथा अकुशलता आई। इस समस्या पर विजय पाने के लिए सरकार ने एक सहमति पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर कर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां को चलाने में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने का निश्चय किया। इसके अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रबंध संपादन में स्वत्वता अधिकार दिए जाएंगे, परंतु वे उत्तरदायी भी होंगे।

उदारीकरण की एक अन्य विशेषता लाइसेंस प्रणाली को हटाने की है। पहले यह अनिवार्य था कि कोई भी निजी व्यक्ति अथवा संगठन कोई औद्योगिक गतिविधि आरंभ करने के लिए सरकार से अनुमति लेगा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित सरकारी विभाग की खिड़की पर भारी भीड़ और लंबी कतार होती थी। इस प्रणाली ने धीरे-धीरे लाइसेंस प्राप्त करने में देरी को जन्म दिया। सरकारी कर्मचारियों ने फाइल निपटाने के लिए रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। इन भ्रष्ट तरीकों ने सरकार को बदनाम किया। अत: 1991 में सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को छोड़ देने का निश्चय किया तथा रुचि रखने वाले व्यक्तियों को अपनी औद्योगिक गतिविधि बिना अनुमति लिए आरंभ करने के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन सामरिक महत्व वाले उद्योगों, जैसे–औषधि, रक्षा उपकरण आदि में अब भी अनुमति की आवश्यकता होती है।

निजीकरण का अर्थ और इसकी आवश्यकता

निजीकरण से अभिप्राय उन औद्योगिक गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र के खोलने से है, जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं, नाभिकीय ऊर्जा और रक्षा को छोड़कर। क्योंकि

मूलभूत और भारी उद्योग वस्तुत: सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत थे, प्रतियोगिता के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरी कंपनियों से प्रतियोगिता के अभाव के कारण उत्पाद तथा सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आई। परिणामस्वरूप, प्रमुख रूप से उपभोक्ता ही हानि उठाते थे, क्योंकि उन्हें अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद नहीं मिलते थे और वितरण प्रणाली तथा अन्य सेवाएं भी बहुत घटिया थीं। अत: सरकार ने उन क्षेत्रों में जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, में निजी क्षेत्र के प्रवेश की स्वीकृति प्रदान करने तथा उसे प्रोत्साहित करने का निश्चय किया। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र का दूरसंचार, नागरिक उड्डयन आदि में प्रवेश हुआ। सरकार ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संपत्तियों के कुछ भाग को जनता को बेचकर उनमें विनिवेश का भी निर्णय लिया।

वैश्वीकरण का अर्थ और इसकी आवश्यकता

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं, श्रम, प्रौद्योगिकी, निवेश आदि के स्वतंत्र प्रवाह के प्रयास किए जाते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO), जो वैश्वीकरण के विकास के लिए शीर्ष एजेंसी है, का सदस्य है। 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए भारत ने नर्म रवैया अपनाया। उसमें वस्तुओं के आयात पर शुल्क कम करने अथवा समाप्त करने के लिए भी अपने आपको प्रतिबद्ध किया। दूसरी तरफ, भारत ने निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए भी नीतियों को अपनाया। सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग की स्थिति में उन्हें 51 प्रतिशत अथवा अधिक अंश रखने की भी स्वीकृति दी, ताकि वे स्वामियों की भांति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यह अद्यतन प्रौद्योगिकी के भारत में स्थानांतरण को भी सुलभ बनाएगा।

पाठगत प्रश्न 2.3

1. उदारीकरण का उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली को बनाए रखना है। (सत्य/ असत्य)
2. निजीकरण नीति बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ाने में सहायता करेगी। (सत्य/असत्य)
3. वैश्वीकरण का उद्देश्य आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना है। (सत्य/असत्य)

2.8 आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां

भारत में आर्थिक नियोजन 1951 में आरंभ किया गया। जैसा कि पहले कहा गया है, आर्थिक नियोजन के कुछ विशेष उद्देश्य थे, जिनमें शामिल हैं–राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के संदर्भ में आर्थिक संवृद्धि की प्राप्ति, रोजगार के स्तर में वृद्धि, आय के वितरण में विषमताओं को दूर करना, गरीबी को हटाना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना आदि। 2014 तक, भारत ने नियोजन के 63 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा बारहवीं योजना काल में प्रवेश किया है। नियोजन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी उपलब्धियों को जानने का यह ठीक समय है। आइए, उनकी चर्चा करें।

1. आर्थिक संवृद्धि में उपलब्धियां

आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करना आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य था। आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रकों के उत्पादन में भी वृद्धि को प्राप्त करना आवश्यक है। विभिन्न योजनाओं का पुनरवलोकन से पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना एक सफलता थी, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आय में 2.1 प्रतिशत वृद्धि दर के लक्ष्य के विपरीत 3.6 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त हुई। फिर, पांचवीं और छठी योजनाओं को छोड़कर अन्य योजना कालों अर्थात् दूसरी से लेकर ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना तक राष्ट्रीय आय में लक्ष्य के अनुसार, वृद्धि दर को प्राप्त नहीं किया जा सका।

इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, परंतु वृद्धि की दर बहुत धीमी है। उदाहरण के लिए, नियोजन के प्रथम 30 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में बहुत धीमी 1.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। हाल में, यह वृद्धि दर कुछ सीमा तक बढ़ी हैं। कृषि में, खाद्यान्नों का उत्पादन प्रथम योजना के आरंभ में 5.1 करोड़ टन से बढ़कर 2011-12 में 25.74 करोड़ टन हो गया है। विशेष रूप से चावल और गेहूं का उत्पादन आश्चर्यजनक रहा है, लेकिन दालों और तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य से नीचे रहा है।

औद्योगिक विकास के संदर्भ में एक प्रमुख उपलब्धि उद्योगों की विविधता रही है। परिवहन तथा दूरसंचार का विस्तार हुआ है, बिजली के उत्पादन और वितरण में वृद्धि तथा इस्पात, एल्यूमीनियम, इंजीनियरिंग माल, रसायन और पैट्रोलियम उत्पादों में यथेष्ठ उन्नति हुई है।

नियोजन की अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में यथेष्ट वृद्धि हुई है। इन उल्लेखनीय वस्तुओं में शामिल हैं–अनाज, चीनी, दूध, अंडे, खाद्य तेल, चाय, कपड़ा तथा बिजली।

2. आधारिक संरचना का सृजन

आधारिक संरचना के सृजन के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि में प्राप्ति की है। सड़कों तथा रेलवे के जालों का विस्तार हुआ है। घरेलू वायु यात्रा में महत्त्वपूर्ण ढंग से वृद्धि हुई है। सिंचाई और जल-विद्युत परियोजनाओं के विस्तार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है। शहरी आधारिक संरचना में वृद्धि के कारण कस्बों और शहरों की स्थापना में वृद्धि हुई है। मोबाइल टेलीफोन एवं इंटरनेट के रूप में दूरसंचार के जाल में अत्यधिक विस्तार हुआ है।

3. शिक्षा में विकास

नियोजन का सबसे अधिक दीप्तिमान क्षेत्र भारत में शिक्षा का विकास रहा है। विद्यालय स्तर पर बच्चों के नामांकन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत में 378 विश्वविद्यालय और 18064 कॉलेज हैं, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास है। भारत में 1.52 लाख उच्चतर माध्यमिक तथा 10.43 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भी हैं।

4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

उपलब्धि का एक अन्य क्षेत्र तकनीकी तथा कुशल मानव शक्ति में वृद्धि के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास रहा है। भारत के अंतरिक्ष विकास को विकसित देशों ने देखा है। इसने नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। आज भारत की विदेशी विशेषज्ञों पर विचार-विमर्श के लिए निर्भरता कम हुई है। इसके विपरीत यह अब मध्य पूर्व तथा अफ्रीका आदि में अनेक देशों में अपने तकनीकी विशेषज्ञ भेजने में सक्षम है।

5. विदेशी व्यापार का विस्तार

देश में औद्योगीकरण के कारण, भारत की पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर निर्भरता कम हुई है। अनेक वस्तुएं, जिनका पहले आयात होता था, अब उनका उत्पादन देश में ही हो रहा है। औद्योगिक उन्नति के कारण भारत अब निर्मित तथा इंजीनियरिंग मॉल का निर्यात करने के भी योग्य है।

पाठगत प्रश्न 2.4

1. किस योजना अवधि में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की वास्तविक दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक थी?

   (अ) द्वितीय योजना (ब) प्रथम योजना

   (स) ग्याहरवीं योजना (द) नौवीं योजना

2. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर 21वीं शताब्दी के आरंभ की अवधि की तुलना में योजना काल के आरंभ की अवधि में अधिक ऊंची थी। (सही या गलत)

2.9 नियोजन की कमियां अथवा असफलताएं

ऊपर बताई गई उपलब्धियों के अतिरिक्त, ऐसे अनेक अधूरे कार्य हैं, जिन्हें भारत में नियोजन को अभी पूर्ण रूप से प्राप्त करना है।

1. गरीबी तथा विषमताओं को पूर्ण रूप से दूर करने में असफलता

नियोजन के 60 वर्षों पश्चात् भी भारत गरीबी को पूरी तरह दूर नहीं कर पाया है। अधिकारिक अनुमानों के अनुसार, 24 करोड़ से भी अधिक लोग अभी भी निरपेक्ष गरीबी में रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी खराब है। सरकार ने गरीबी हटाने के अनेक उपाय किए हैं, लेकिन अभी तक वे बहुत सफल नहीं रहे हैं।

इसी प्रकार, आय और परिसंपत्तियों के वितरण में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। फलस्वरूप विषमताएं विद्यमान हैं। भूमि जोतों वाली संख्या की तुलना में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या

बहुत अधिक है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने कुछ बड़े औद्योगिक घरानों की सहायता की है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हो गई है। यदि भारत समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना चाहता है तो इस प्रवृत्ति को उलटना चाहिए।

2. बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है

आय और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, भारत में रोजगार की स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है। जनसंख्या तथा श्रम शक्ति में तीव्र वृद्धि के कारण समस्या और भी गंभीर हो गई है। अधिकारिक अनुमानों के अनुसार, भारत की बेरोजगारी की दर 6.6 प्रतिशत है। प्रत्येक वर्ष आवश्यक मात्रा में नौकरियों के सृजन के अभाव में बड़ी मात्रा में संचित बेरोजगारी भी पाई जाती है।

3. भ्रष्टाचार तथा काले धन को कम करने में असफलता

विभिन्न सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार भारत में एक गंभीर चिंता का विषय है। एक साधारण व्यक्ति को बिना रिश्वत दिए अपना काम कराने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में, चुनावों में भ्रष्टाचार एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों में शामिल हैं–रिश्वत लेना या देना, सरकार को कर का भुगतान न करना, ठेका प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दबाव, विक्रेताओं में कीमत बढ़ाने के लिए गुप्त समझौता आदि। भ्रष्टाचार ने काले धन को जन्म दिया है, जिसे कहीं भी हिसाब-किताब में नहीं लाया जाता, परंतु चलन में रहता है। भारत के GDP का बहुत बड़ा भाग बिना हिसाब-किताब वाला है। काले धन से मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है और समाज में दबाव उत्पन्न होता है। यह आय के वितरण में विषमता का एक मूल कारण है, क्योंकि वे लोग जिनके पास काला धन होता है, साधारण नागरिकों के कारण धनवान बन जाते हैं।

आपने क्या सीखा

- भारत ने विभिन्न आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए 1951 से आरंभ करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया।
- नियोजन के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं–आर्थिक संवृद्धि, रोजगार में वृद्धि, विषमताओं तथा गरीबी को दूर करना तथा सामाजिक न्याय और समानता को प्राप्त करना।
- इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूलभूत तथा भारी उद्योगों पर बल देते हुए भारत ने औद्योगीकरण की व्यूह रचना को अपनाया।
- नियोजन की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की गई, फिर भी वृद्धि की दर लक्षित दर से कम है।

- भारत की आधारिक संरचना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और विदेशी व्यापार में उन्नति उल्लेखनीय रही है।
- भारत में नियोजन की महत्त्वपूर्ण कमियां हैं–गरीबी, विषमता तथा बेरोजगारी को पूर्ण रूप से दूर करने में असमर्थता।
- सार्वजनिक स्थानों में भ्रष्टाचार तथा काले धन का प्रचलन भारत में विकास के लिए प्रमुख खतरे हैं।
- औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने, तीव्र गति से आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए 1991 में सरकार ने नई आर्थिक नीति को अपनाया।
- नई आर्थिक नीति को LPG मॉडल कहते हैं, अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण।
- LPG नीति का उद्देश्य है–लाइसेंस नीति को समाप्त करना, बाजार में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना तथा विश्व में स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित करना।

पाठांत प्रश्न

लघु उत्तर प्रश्न

1. नियोजन का अर्थ बताइए।
2. भारत में नियोजन के दो उद्देश्य लिखिए।
3. नियोजन के लिए आवश्यक दो प्रकार के संसाधनों के उदाहरण सहित नाम दीजिए।
4. औद्योगीकरण की व्यूह रचना को अपनाने के लिए एक औचित्य बताइए।

दीर्घोत्तर प्रश्न

1. नियोजन की प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए।
2. विषमता तथा गरीबी दूर करने के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए।
3. भारत ने योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन-सी व्यूह रचना अपनाई और क्यों?
4. भारत में नियोजन के अंतर्गत आर्थिक संवृद्धि तथा रोजगार में वृद्धि के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
5. भारत में आर्थिक नियोजन की तीन उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए।

6. गरीबी तथा विषमताओं को हटाने में नियोजन के निष्पादन का मूल्यांकन कीजिए।
7. आर्थिक संवृद्धि के संदर्भ में नियोजन की उपलब्धि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
8. भारत में आधारिक संरचना के विकास पर टिप्पणी कीजिए।
9. नई आर्थिक नीति अपनाने के कारण दीजिए।
10. आर्थिक संवृद्धि में उन्नति करने के लिए सरकार के LPG मॉडल की व्याख्या कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

2.1

1. (अ)   2. (ब)   3. (स)   4. (द)

2.2

1. (अ)   2. (ब)

2.3

1. असत्य   2. सत्य   3. असत्य

2.4

1. (ब)   2. असत्य